Drishti IAS

करेंट अफेयर्स बिहार

नवम्बर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

- डायट की गतिविधियों में में बिहार शीर्ष तीन राज्यों में शामिल 3
- CBSE ईस्ट ज़ोन जूडो चैंपियनशिप में पटना के श्वेतांक ने जीता बेस्ट जुडोका अवार्ड 3
- बिहार विधानसभा में 26,086 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश 4
- बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ में जीता स्वर्ण पदक 5
- बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी 6
- 'बिहार बिजनेस कनेक्ट' समिट 6
- विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास 7
- सीवान की युसरा फातमा का इंडिया बुक ऑफ रिकाड्र्स में नाम दर्ज 8
- 25 नवंबर से शुरू होगा बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 9
- अयोध्या के बाद अब विकसित होगा, सीता जन्मस्थली मिथिला का पुनौरा धाम 10
- 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' की पहली किस्त के लिये राशि जारी 11
- विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में मधुबनी अव्वल और नालंदा सबसे नीचे 12
- बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया 12
- फरक्का-कहलगाँव से जगमग होगा बिहार, तीन सरेंडर इकइयो से मिलेगी 159 मेगावाट बिजली 13
- मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार 13
- बिहार में शराबबंदी के आकलन के लिये होगा हर घर सर्वे 14
- मुख्यमंत्री ने दरभंगा में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन 14
- बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया मॉडल टाइम टेबल 15
- 'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' की अधिसूचना हुई जारी 15

नोट :

बिहार

डायट की गतिविधियों में में बिहार शीर्ष तीन राज्यों में शामिल

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों के डायट की गतिविधियों के आधार पर अक्तूबर की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बिहार शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है। इसमें केरल पहले तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- पिछले दो सालों में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने लगातार बिहार के सभी डायट को शैक्षणिक विकास में लगा रखा है। शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार रैंकिंग जारी की है ताकि यह पता चल सके कि शैक्षणिक कार्य में डायट का सहयोग कितना महत्त्वपूर्ण है।
- दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों को नई तकनीक बताने में बिहार के डायट सबसे ऊपर हैं। बिहार में 33 ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, विकास के लिये डिजिटल कोर्स का निर्माण, संचालन का माध्यम डायट है।
- पहले चरण में राज्य के सभी 33 डायट को शामिल कर डिजिटल कोर्स तैयार किया गया। डिजिटल कोर्स तैयार करने और उसका संचालन करने में बिहार देश में पहले पायदान पर है। यहाँ के सभी डायट ने अपना डिजिटल कोर्स डिजाइन और लॉन्च किया है।
- पिछले एक साल में दो लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही ज़िला स्तर पर छोटे-छोटे कोर्स डिजाइन किये गए। इससे शिक्षक ऑनलाइन जुड़कर इन कोर्स को कर पाते हैं।
- दीक्षा पोर्टल से राज्य के कुल 93 हज़ार 670 शिक्षक जुड़ चुके हैं। इन शिक्षकों को अब किसी कोर्स को करने के लिये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है।

CBSE ईस्ट ज़ोन जूडो चैंपियनशिप में पटना के श्वेतांक ने जीता बेस्ट जुडोका अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर, 2023 को पटना के नॉलेजग्राम कैंपस में सीबीएसई ईस्ट ज़ोन जूडो चैंपियनशिप संपन्न हुआ, जिसमें पटना के छात्र श्वेतांक ने बेस्ट जुडोका अवार्ड अपने नाम किया।

प्रमुख बिंदु

- सीबीएसई ज़ोनल जूडो चैंपियनशिप में बेस्ट जुडोका अवार्ड (छात्रा) पर उत्तर प्रदेश की छात्रा अदिति शर्मा ने कब्जा जमाया।
- विदित हो कि 28 से 31 अक्तूबर, 2023 तक पटना के नॉलेजग्राम कैंपस में सीबीएसई ईस्ट ज़ोन जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया।
- जूडो चैंपियनशिप में 49 KG भार वर्ग में प्रतियोगिताएँ संपन्न हुईं। कुल 392 मेडल्स (स्वर्ण, रजत एवं काँस्य पदक) वितरित किये गए।
- चैंपियनशिप की विशिष्ट वैजयंतियों के विजेता :
  - बेस्ट जुडोका अवार्ड (छात्रा): अदिति शर्मा, रेडिएंट सेंट्रल एकेडमी, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश
  - बेस्ट जुडोका अवार्ड (छात्र) : श्वेतांक, ओपेन माइंड्स बिरला स्कूल, दानापुर, पटना, बिहार
  - चैंपियनशिप 1st पोजिशन : रेडिएंट सेंट्रल एकेडमी, जलालपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश
  - चैंपियनशिप 2nd पोजिशन : एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल, बोकारो, झारखंड
  - चैंपियनशिप 3rd पोजिशन : गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, बोकारो, झारखंड

नोट :

- ग्रुप चैंपियन (अंडर 11 छात्र) : ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा, झारखंड
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 14 छात्र) : ओपन माइंड्स बिरला स्कूल, दानापुर, पटना, बिहार
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 17 छात्र) : रेडिएंट सेंट्रल एकेडमी, जलालपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 19 छात्र) : रेडिएंट सेंट्रल एकेडमी, जलालपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 11 छात्रा) : दिल्ली पब्लिक स्कूल, इटावा, उत्तर प्रदेश
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 14 छात्रा) : गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, बोकारो, झारखंड
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 17 छात्रा) : एमजीएम हायर सेकेंडरी, बोकारो, झारखंड
- ग्रुप चैंपियन (अंडर 19 छात्रा) : एमजीएम हायर सेकेंडरी, बोकारो, झारखंड

बिहार विधानसभा में 26,086 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2023 को बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 26,086 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसके साथ ही बिहार राज्य माल एवं सेवा कर विधेयक 2023 भी पटल पर रखा गया।

प्रमुख बिंदु

- विदित हो कि नौ महीने में नीतीश सरकार द्वारा पेश किया गया ये दूसरा अनुपूरक बजट है। वित्त मंत्री विजय चौधरी द्वारा फरवरी में 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। जिसके बाद मॉनसून सत्र में 10 जुलाई को 43,774 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था।
- 26,086 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट के बाद बिहार का कुल बजट अब 3.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
- पेश किये गए अनुपूरक बजट 2023-24 के 26,086 करोड़ रुपए में से वार्षिक स्कीम मद में 16 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक, स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 60 करोड़ रुपए शामिल है।
- अनुपूरक बजट में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम में केंद्रांश के लिये वार्षिक योजना मद के 16000 करोड़ रुपए में से केंद्र प्रायोजित योजना का केंद्रांश 2,288 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 4,828 करोड़ रुपए यानी कुल राशि 7,116 करोड़ रुपए है।
- राज्य स्कीम में वार्षिक योजना मद के 16000 करोड़ रुपए में से राज्य की योजना के लिये कुल राशि 8,900 करोड़ रुपए है।

नोट :

बिहार की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2023 को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चल रहे 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के गोपालगंज ज़िले की दुर्गा सिंह ने अंडर-18 दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 से 9 नवंबर तक 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हो रहा है।
- दुर्गा सिंह ने अंडर-18 आयु वर्ग में 1500 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत कर बिहार के लिये पदकों का खाता खोला है।
- दुर्गा सिंह ने 1500 मीटरकी दौड़ 4:38. 29 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता है।
- दुर्गा ने यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय कोच एवं फिजिकल एक्सपर्ट राकेश सिंह की ट्रेनिंग एवं मार्गदर्शन में हासिल की है।

नोट :

बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 75 फीसदी किए जाने पर सहमति दी गई। अब इस बिहार आरक्षण बिल 2023 को विधानमंडल से पास कराया जाएगा।
- कैबिनेट से पास बिल में आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा। इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ कर 75 फीसदी हो जाएगी और पहले के 40 प्रतिशत की जगह अब 25 फीसदी सीटें सामान्य वर्ग के लिये होंगी।
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 18 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
- अनुसूचित जाति (एससी) को 16 फीसदी आरक्षण की जगह 20 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पहले से मिल रहे 1 फीसदी आरक्षण की जगह 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया है।
- इसके अलावा, कैबिनेट ने बैठक में 94 लाख से अधिक गरीबों को स्वरोज़गार के लिये मुफ्त दो लाख रुपए सतत जीवीकोपार्जन योजना के प्रस्ताव को सहमति दे दी है।
- कैबिनेट में पीएम आवास (ग्रामीण) के लिये भूमिहीन परिवारों को अब जमीन खरीदने के लिये 60 हज़ार रुपए की जगह पर एक लाख रुपए देने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई।

'बिहार बिजनेस कनेक्ट' समिट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आईटीसी मौर्य, नई दिल्ली में 'बिहार बिजनेस कनेक्ट'समिट का आयोजन किया गया। समिट में इंडस्ट्री लीडरों और सरकारी अधिकारियों ने एक मंच पर बिहार में निवेश के अवसरों को तलाशने पर चर्चा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस समिट का उद्देश्य बिहार के चार प्रमुख क्षेत्रों- कपड़ा और चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम तथा सामान्य विनिर्माण में विशेष ध्यान देते हुए निवेश संभावनाओं को रेखांकित करना था। ये क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप निवेश और विकास के पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करते हैं।
- इस कार्यक्रम में बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि अब तक 28 विभिन्न कंपनियों ने राज्य में इथेनॉल उत्पादन में रूचि दिखाई है। इन सबने औसतन 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अंतिम मंज़ूरी दे दी है। वेदांता 50 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है, और निकट भविष्य में दो और सौर ऊर्जा संयंत्रों की योजना है।
- बिहार सरकार ने निवेशकों के ज़रिये राज्य में इथेनॉल उत्पादन में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे बिहार के इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरने की संभावना है। साथ ही इससे राज्य के किसानों को बड़ा लाभ पहुँचने की उम्मीद है।
- बिहार के उद्योग मंत्री ने 13-14 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाले आगामी बिजनेस कनेक्ट समिट 2023 में शामिल होने के लिये उद्यमियों को निमंत्रण भी दिया।

विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2023 को बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल-2023 पास हो गया। इसके अस्तित्व में आने पर एससी, एसटी और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये) अधिनियम और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण अधिनियम में संशोधन की मंज़ूरी दे दी।
- संशोधित अधिनियम के तहत दोनों मामलों में अनुसूचित जातियों को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजातियों को दो फीसदी, पिछड़ा वर्ग को 18 फीसदी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25 फीसदी सहित कुल 65 फीसदी आरक्षण रहेगा। इसके अलावा केंद्रीय अधिनियम के तहत पहले से स्वीकृत इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10 फीसदी का आरक्षण मिलता रहेगा।
- 10 नवंबर को यह दोनों विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश किये जायेंगे। विधान परिषद में पास होने के बाद बिहार की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

नोट :

सीवान की युसरा फातमा का इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार के सीवान ज़िले की यूसरा फातमा सबसे कम उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है, जिसके लिये उसका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सीवान ज़िला के बरहड़िया प्रखंड़ अंतर्गत तेतहली गाँव की यूसरा फातमा ने मात्र 15 साल 6 महीने की उम्र में चार काव्य लिखकर यह उपलब्धि हासिल की है।
- इस रिकॉर्ड के साथ वह किशोर अवस्था में सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली लड़की बनी है। युसरा आठ वर्ष की उम्र से कविताएँ लिख रही है। 12 वर्ष की उम्र में उसने पहली काव्य पुस्तिका लिखी थी।
- युसरा ने अपनी हिंदी कविताओं के माध्यम से समाज को आईने के रूप में रखने की कोशिश की है। इसके अलावा समाज को जागरूक करते हुए लिखा है, कि चलचित्र से केवल चित्र नहीं देखे बल्कि उसका चरित्र देखे और अनुसरण करें।
- युसरा ने चार काव्य किताब लिखी है जिसमें 'जज्बा', 'मेरे हिस्से की कोशिश', 'शाम और तन्हाई', और 'बेरुखी'काव्य संग्रह शामिल है।

नोट :

25 नवंबर से शुरू होगा बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के हरिहर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ 25 नवंबर को होगा तथा यह 26 दिसंबर (32 दिनों) तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- सोनपुर मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जो बिहार के सारण और वैशाली ज़िले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में दो नदियों, गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है।
- पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन काल से लोकप्रिय, यह महीने भर चलने वाला आयोजन नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर शुरू होता है।
- हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ शुरू होने वाले इस मेले को 'हरिहर क्षेत्र मेला'के नाम से भी जाना जाता है जबकि स्थानीय लोग इसे 'छत्तर मेला'कहते हैं। हिंदू भक्त गंगा और गंडक नदी में पवित्र डुबकी लगाने के लिए क्षेत्र में आते हैं और हरिहर नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं।
- यह मेला भले ही पशु मेला के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि यहां सूई से लेकर हाथी तक की खरीदारी की जा सकती है।
- इस मेले का ऐतिहासिक महत्त्व भी है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में मध्य एशिया से पशुओं की खरीदारी करने कारोबारी आया करते थे और यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से हाथियों की खरीद की थी।
- सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इसके अलावा सिख धर्म के गुरु नानक देव के यहाँ आने का जिक्र धर्मों में मिलता है और भगवान बुद्ध भी यहां अपनी कुशीनगर की यात्रा के दौरान आये थे।
- सोनपुर की इस धरती पर हरिहर नाथ मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हरि (विष्णु) और हर (शिव) की एकीकृत मूर्ति है। इसके मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कभी ब्रह्मा ने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ ही संगम किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली की मूर्ति में शुंग काल का स्तंभ है।

नोट :

अयोध्या के बाद अब विकसित होगा, सीता जन्मस्थली मिथिला का पुनौरा धाम

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी ज़िला के पुनौरा धाम को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि पुनौरा धाम को विकसित करने के संबंध में राज्य पर्यटन विकास निगम ने टेंडर निकाला है। टेंडर की पूरी प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक पूरी हो जाएगी। वहीं, योजना पूरा करने की अवधि 24 महीने निर्धारित की गई है।
- पुनौरा धाम विकास योजना पर 67.39 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से किया जाएगा।
- राज्य सरकार पुनौरा धाम को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यहाँ सभी तरह की जरूरी सुविधाओं का विकास होगा। इसके बाद यह जन्मस्थली धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। पूरे देश-दुनिया से भी यहां श्रद्धालु पहुँचेंगे।
- विदित हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में कैबिनेट की बैठक में सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के जन्मस्थान के विकास के लिये 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी।
- योजना के अनुसार 72 करोड़ की राशि से पुनौरा धाम को विश्वस्तरीय सुविधा से लैश और सुसज्जित किया जाएगा। इसके तहत कॉलमयुक्त कोलोनेड परिक्रमा पथ का निर्माण, सीता वाटिका, लव-कुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
- मंदिर परिसर में सुंदर वास्तुशिल्प से सुसज्जित दीवारें होंगी। मंडप व आंतरिक सड़क का निर्माण किया जाएगा। मंदिर में आने वाले स्थानीय व बाहरी श्रद्धालुओं के वाहनों लगाने के लिये अत्याधुनिक पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिये आवासन, खान-पान आदि की भी व्यवस्था की जाएगी।
- मंदिर परिसर में माता सीता पर आधारित थ्रीडी एनिमेशन शो का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही डिस्प्लेकियोस्क व पाथ-वे भी बनाया जाएगा। बच्चों के लिये अलग सेप्लेएरिया डेवलप किया जाएगा, जिससे बच्चे खेल-खेल में माता सीता के संबंध में जानकारी प्राप्त करें।
- पूरे मंदिर परिसर में बेहतर भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला एवं अन्य कलात्मक कार्य किये जाएंगे, जिससे कि पर्यटक आकर्षित हों। इन कलाओं के माध्यम से माता सीता के जीवन की भी जानकारी होगी। साथ ही, लैंडस्केपिंग व थिमेटिक गेट भी बनाएँ जाएँगे।

नोट :

'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' की पहली किस्त के लिये राशि जारी

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के लिये राशि जारी कर दी।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' के तहत 2023-24 के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया गया है। पहली किस्त के रूप में चार-चार लाख रुपए भेजे गए।
- विदित हो कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री उद्यमी अनुदान योजना है।
- इस योजना के तहत उद्योग के लिये लोगों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर 50% सब्सिडी भी दी जाती है। साथ ही ट्रेनिंग के लिये 25 हज़ार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है। लोगों को सात साल में ऋण चुकाना होता है।
- 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' के तहत पहली किस्त में 4 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 4 लाख रुपए और तीसरी किस्त में 2 लाख रुपए दिये जाते हैं।

नोट :

विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में मधुबनी अव्वल और नालंदा सबसे नीचे

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2023 को श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में ज़िलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने में मधुबनी ज़िला अव्वल जबकि नालंदा ज़िला सबसे निचले पायदान पर है।

प्रमुख बिंदु

- श्रम संसाधन विभाग की इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर दरभंगा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर ज़िला है।
- ज़िलों की क्रमवार रैंकिंग है- मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भभुआ, शेखपुरा, पूर्णिया, सारण, जमुई, बेगूसराय, औरंगाबाद, बक्सर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, अरवल, वैशाली, रोहतास, किशनगंज, मुंगेर, सीवान, जहानाबाद, नवादा, अररिया, सुपौल, पश्चिम चंपारण, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गया, सहरसा, पटना, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, बांका, नालंदा।
- विभाग की ओर पिछले तीन माह से ज़िलों की मासिक रैंकिंग बनाई जा रही है, लेकिन पहली बार अक्तूबर में रैंकिंग को पब्लिक डोमेन में डाला गया है। अब विभाग ने निर्णय लिया है कि लगातार, जिस ज़िले की रैंकिंग खराब होगी, उस ज़िले के श्रम अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।
- अधिकारियों के मुताबिक विभाग की योजनाओं के नौ मानकों पर ज़िलों का चयन किया गया है।
  - लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिये 20 अंक
  - भवन निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिये 15 अंक
  - भवन निर्माण से संबंधित सभी मज़दूरों के कार्य ऑनलाइन निबटाने के लिये 15 अंक
  - असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 10 अंक
  - बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों के लिये 10 अंक
  - श्रम प्रवर्तन कार्यालय पर निगरानी के लिये 10 अंक
  - कर वसूली के लिये 10 अंक
  - विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्स्थापन के लिये 5 अंक
  - प्रवासी कामगारों के लिये 5 अंक

बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद (एसआइपीबी) की 50वीं बैठक में 820.76 करोड़ रुपए के कुल 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है। सभी प्रस्ताव दो करोड़ रुपए से अधिक के हैं।

प्रमुख बिंदु

- बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की यह बैठक 10 नवंबर को हुई थी, जिसकी प्रोसीडिंग 17 नवंबर को जारी की गयी।
- परिषद द्वारा जिन निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है उनमें सर्वाधिक 14 प्रस्ताव (490 करोड़ रुपए) खाद्य प्रसंस्करण के हैं। इसके अलावा 13 प्रस्ताव (157.23 करोड़ रुपए) राइस मिलों की स्थापना के लिये, 12 प्रस्ताव (115 करोड़ रुपए) जनरल मैन्युफैक्चरिंग के, 4 प्रस्ताव (38 करोड़ रुपए) हेल्थ एंड केयर सेक्टर के, एक प्रस्ताव (102 करोड़ रुपए) टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर का, एक प्रस्ताव (5.61 करोड़ रुपए) आइटी सेक्टर का और एक प्रस्ताव (3.91 करोड़ रुपए) स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है।
- राज्य के वैशाली ज़िले में 102 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लेदर फुटवियर बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। साथ ही 191 करोड़ रुपए के निवेश से लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- हाजीपुर में 61 करोड़ रुपए के निवेश से बिस्कुट एंड केक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। पटना में पाटलिपुत्र रोड क्षेत्र में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी निवेश करने जा रही है।

नोट :

- भागलपुर और पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इसके अलावा नौ ज़िलों- नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, पटना, बक्सर और शेखपुरा में नयी राइस मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- भागलपुर के नौगछिया में 58 करोड़ रुपए के निवेश और पूर्णिया के परौरा में 17.30 करोड़ रुपए के निवेश से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बेगूसराय में वाटर पार्क/होटल/रेस्टोरेंट स्थापित करने में लगभग 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
- पटना में फूड लैब की स्थापना में करीब छह करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश में होटल स्थापित किया जाएगा। शेष निवेश फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किये जाएंगे।
- एसआइपीबी की बैठक में 216.85 करोड़ रुपए के 28 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस भी दिया गया है। ये वे प्रस्ताव हैं, जिनमें निवेश के लिये वित्तीय मदद देने के लिये बैंक और अन्य वित्तीय एजेंसियाँ तैयार हैं। इस तरह का क्लियरेंस उन यूनिटों को दिया जाता है, जिन्हें वित्तीय एजेंसियां लोन और दूसरी सुविधाएं देने के लिये अंतिम रूप से तैयार हो जाती हैं।

फरक्का-कहलगाँव से जगमग होगा बिहार, तीन सरेंडर इकइयो से मिलेगी 159 मेगावाट बिजली

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2023 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने फरक्का और कहलगांव की उत्पादन इकाईयों से 24 घंटे 159 मेगावाट बिजली आपूर्ति के संबंध में दायर बिजली कंपनियों की याचिका पर निर्णय देते हुए बिजली खरीद की अनुमति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्रालय की पूर्वी क्षेत्र विद्युत समिति के आदेश पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने मुहर लगते हुए बिजली कंपनियों कप खरीद की मंज़ूरी दी है। यह बिजली केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा पहले से अनुमोदित दर पर उपलब्ध होगा।
- बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (तकनीकी) अरुण सिन्हा और सदस्य (विधि) पी एस यादव की बेंच ने इससे जुडी बिजली कंपनियों की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्त्ताओं को फरक्का के स्टेज-वन और स्टेज-टू इकाई से 107.751 मेगावाट और एनटीपीसी की कहलगांव इकाई से 51.520 मेगावाट 24 घंटे उपलब्ध करायी जाएगी। बिजली कंपनी ने एक महीने पहले ही फरक्का की दो और कहलगांव की एक इकाई से लगभग 850 मेगावाट बिजली सरेंडर की थी।
- देश के पूर्वी राज्यों की बिजली आपूर्ति नियंत्रित करने वाली संस्था ने बिहार की सरेंडर बिजली में से किसी अन्य राज्य को आवंटित नही हुयी 159 मेगावाट बिजली पुन: बिहार को उपलब्ध कराया है। इसके लिये एनटीपीसी एवं बिहार सरकार के मध्य समझौता हुआ है जिसमे सरेंडर की गई अनावंटित बिजली संबंधित राज्य को ही उपयोग करना होता है।
- याचिका में बिजली कंपनियों ने बताया कि बरौनी स्टेज वन में निर्मित 110-110 मेगावाट की दो इकाईयाँ पिछले 14 महीनो से अनुबंधित मात्रा का केवल 5 प्रतिशत ही आपूर्ति कर रही है। इस स्थिति में भविष्य में सुधार होने कि संभावना नहीं है जिससे बिजली में 'राउंड द क्लाक'के आधार पर करीब 200 मेगावाट की वर्ष भर कमी रह रही है।
- बिजली कंपनियों ने कहा कि 159 मेगावाट बिजली की खरीद अनुमति मिलने से बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन से लगभग 200 मेगावाट की कमी को कम करने में सहायता मिलेगी।

मछली के मामले में आत्मनिर्भर हुआ बिहार

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में वर्तमान में प्रत्येक साल प्रति व्यक्ति 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है। कतला मछली बिहारियों की पहली पसंद है। वहीं रोहू दूसरे स्थान पर तथा मृगल (नैनी) का तीसरा स्थान है।

नोट :

- कतला मछली का बिहार में उत्पादन 164.189 हज़ार मीट्रिक टन है। रोहू का उत्पादन 154.794 हज़ार मीट्रिक टन तथा मृगल का उत्पादन 107.586 हज़ार मीट्रिक टन है।
- पंगेशियस, कॉमन, सिल्वर और ग्रास कार्प का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 6.464 किलोग्राम मछली खा जाता है।
- राज्यभर से अभी 37.0545 हज़ार मीट्रिक टन मछलियाँ दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं जबकि 38.462 हज़ार मीट्रिक टन दूसरे राज्यों से बिहार में मछलियाँ आ रही हैं।
- राज्य में सिल्वर कार्प का उत्पादन 80.4113 हज़ार मीट्रिक टन, ग्रास कार्प का 96.49262 हज़ार मीट्रिक टन, कॉमन कार्प का 92.66252 हज़ार मीट्रिक टन, कैट फीस का 45.8596 हज़ार मीट्रिक टन तथा पंगेशियस मछली का उत्पादन 52.8796 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो रहा है। साथ ही अन्य मछलियों का उत्पादन 48.5901 हज़ार टन प्रतिवर्ष हो रहा है।
- मछली उत्पादन में बिहार अब देश के शीर्ष 04 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान शेखपुरा ज़िले का है। सरकार के आर्थिक सहयोग की वजह से शेखपुरा ज़िला जमुई, नालंदा, नवादा, लखीसराय, पटना, बेगूसराय आदि ज़िलों को ताजी मछली उपलब्ध करा रहा है।

बिहार में शराबबंदी के आकलन के लिये होगा हर घर सर्वे

चर्चा में क्यों ?

26 नवंबर, 2023 को नशामुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना की तरह शराबबंदी के प्रभाव के आकलन के लिये अब हर घर में सर्वे होगा। उन्होंने मद्य निषेध के प्रचार के लिये वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई।

प्रमुख बिंदु

- फरवरी 2023 में जारी किये गए सर्वे के अनुसार 99 प्रतिशत महिलाएँ और 92 प्रतिशत पुरुष शराबबंदी पक्ष में हैं।
- इस सर्वे के माध्यम से यह पता चलेगा कि कितने लोगों ने शराब का सेवन छोड़ा है। साथ ही शराबबंदी का परिवार और समाज पर प्रभाव की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।
- मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार इस बार अकादमिक संस्थानों को इसके लिये आमंत्रित किया गया है।
- बिहार के सभी 38 ज़िलों के न्यूनतम 2500 घरों का सर्वे किया जाएगा। साथ ही कम-से-कम 40 लोगों का इंटरव्यू भी किया जाएगा। इसके आलावा चार फोकस ग्रुप भी होंगे, जो शराबबंदी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे।
- वर्ष 2018 के सर्वे से यह ज्ञात हुआ कि 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है तथा वर्ष 2023 के सर्वे में यह आँकड़ा 1 करोड़ 82 लाख पर पहुँच गया।

मुख्यमंत्री ने दरभंगा में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2742.04 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को पुनर्विकसित करने की योजना अंतर्गत प्रति वर्ष 250 नामांकन के शैक्षणिक भवन एवं 2100 शैय्या के अस्पताल तथा राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा के निर्माण का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 194.08 करोड़ रुपए की लागत से 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया।
- मुख्यमंत्री ने सर्जरी ब्लॉक में 'दीदी की रसोई' का भी शुभारंभ किया। इसके पश्चात् सर्जरी ब्लॉक एवं प्रसव कक्ष का मुख्यमंत्री ने मुआयना किया।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का और विस्तार किया जा रहा है। इसमें पहले से 400 बेड का अस्पताल बना हुआ है। यहाँ जब 2500 बेड का अस्पताल बन जाएगा तो यहाँ इलाज़ और बेहतर ढंग से होगा साथ ही मेडिकल की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से होगी।

बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया मॉडल टाइम टेबल

चर्चा में क्यों ?

28 नवंबर, 2023 को बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिये मॉडल टाइम टेबल जारी किया गया है। यह 1 दिसंबर से सभी विद्यालयों में समान रूप से प्रभावी होगा।

प्रमुख बिंदु

- मॉडल टाइम टेबल के अनुसार विद्यालय सुबह 9:00 बजे खुलेगा। सुबह 9:00 से 9:30 बजे तक प्रार्थना योगाभ्यास, व्यायाम एवं ड्रिल होगी।
- पहली घंटी 9:30 से 10:10 तक, दूसरी 10:10 से 10:50 तक, तीसरी 10:50 से 11:30 तक, चौथी 11:30 से 12:10 तक होगी।
- एमडीएम एवं मध्यांतर 12:10 से 12:50 तक होगा। इसके बाद पाँचवी घंटी 12:50 से 1:30 तक, छठी घंटी 1:30 से 2:10 तक, सातवी घंटी 2:10 से 2:50 तक, आठवी घंटी 2:50 से 3:30 तक रहेगी।
- पहली घंटी सुबह 9:30 बजे प्रारंभ होगी तथा छात्र-छात्राओं की छुट्टी अपराह्न 3:30 बजे होगी।
- आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस टाइम टेबल के जरिये स्कूल बंद होंगे और शुरू होंगे। स्कूल अपने स्तर पर इस टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे, अगर स्कूल में किसी कक्षा की बोर्ड या सेंटअप परीक्षा हो रही है तो अन्य कक्षाएँ निलंबित नहीं की जाएंगी।
- शनिवार को पूरे दिन चहल-पहल रहेगी, भोजनावकाश के बाद शिक्षण कार्य होगा। इसके बाद बाल संसद और अभिभावकों के साथ बैठक होगी।
- संस्कृत बोर्ड स्कूल और सरकारी उर्दू स्कूल भी उपरोक्त मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे। मिशन दक्ष की तरह दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:15 बजे तक विशेष कक्षाएँ संचालित की जाएंगी। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को छोड़कर शाम 4.15 से 5.00 बजे तक होमवर्क चेक किया जाएगा, पाठ्य टिप्पणी तैयार की जाएगी, मिशन दक्ष की कक्षाएँ ली जाएंगी। शिक्षकों की छुट्टी 5 बजे होगी।
- अपर मुख्य सचिव पाठक ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक को अधिकतम पाँच बच्चों को पढ़ाना होगा। शिक्षकों को इतने बच्चों को गोद लेना होगा। इन शिक्षकों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे जिस कक्षा में नामांकित हैं, उस कक्षा का बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ज्ञान दें।
- यह पूरी कवायद 'मिशन दक्ष' के तौर पर संचालित की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने में बेहद कमजोर कक्षा 3 से 8 तक के 25 लाख से अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिये विशेष कक्षाएँ लगाई जाएंगी।
- अपर मुख्य सचिव पाठक ने ज़िला अधिकारियों से कहा है कि अप्रैल 2024 में ज़िला स्तर पर 25 लाख बच्चों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि ये बच्चे उस परीक्षा में फेल हो गये, तो संबंधित प्रधानाध्यापक व शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी कवायद की ज़िम्मेदारी ज़िला अधिकारियों को सौंपी गई है।

'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' की अधिसूचना हुई जारी

चर्चा में क्यों ?

29 नवंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के परिवहन विभाग ने 'मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना' की अधिसूचना जारी की है। इस योजना का संचालन 2025-26 तक होगा।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों को बस की खरीद के लिये पाँच लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।
- विभागीय जानकारी के अनुसार, योजना के तहत लाभुकों के चयन के लिये प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। इसमें जाति के बाद वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता होगी। अधिकतम अंक वालों को वरीयता दी जाएगी।

नोट :

- अंक समान होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता मिलेगी। योजना का लाभ पाने के लिये आवेदन आनलाइन प्राप्त किये जाएंगे, जिसका लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, मैट्रिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी। इसके बाद आवेदक को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। खरीदे गए वाहन को पाँच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति लिये बेचा नहीं जा सकेगा।
- विभाग के अनुसार, तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुकों के चयन के लिये तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष ज़िला पदाधिकारी होंगे, जबकि उप-विकास आयुक्त और ज़िला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे।
- बस की खरीद के बाद उससे जुड़े कागजात डीटीओ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक जाँच के बाद डीटीओ के द्वारा लाभुक के खाते में ऑनलाइन राशि भेजी जाएगी।

नोट :